झूठ के आसमान में, रफाल की कीमतों का उड़ता सच

'द हिंदू' की रिपोर्ट, रवीश कुमार की प्रस्तुति

सरकार जिस रफाल विमान को 9% सस्ते दर पर ख़रीदने की बात करती है, दरअसल वह झांसा दे रही है।

द हिन्दू में छपी विख्यात पत्रकार संपादक N Ram की रिपोर्ट से तो यही लगता है. N Ram कहते हैं कि प्रति विमान 41.42% अधिक दाम देकर खरीदे जा रहे हैं.

इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद लगता है कि कीमतों को लेकर संसद में हुई बहस अंतिम नहीं है.

मोदी सरकार का तर्क रहता है कि....भारत और फ्रांस के बीच जो करार हुआ है उसकी गोपनीयता की शर्तों के कारण कीमत नहीं बता सकते. मगर उस करार में कहा गया है कि....गोपनीयता की शर्तें रक्षा से संबंधित बातों तक ही सीमित हैं. यानी कीमत बताई जा सकती है. कीमत क्लासिफाइड सूचना नहीं है.

विवाद से पहले जब डील हुई थी तब सेना और सिविल अधिकारियों ने मीडिया को ब्रीफ किया था और बकायदा कीमत बताई थी.

N Ram बताते हैं कि जब 2007 में दास्सों एविशन को लंबी प्रक्रिया के बाद चुना गया तब यही तय हुआ कि 18 विमान सुसज्जित अवस्था में आएंगे और 108 हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड तैयार करेगा. उस वक्त दास्सों ने एक विमान के लिए 79.3 मिलियन यूरो मांगा था. 2011 में यह कीमत 100.85 मिलयन यूरो हो गई.

बेशक 2016 में 2011 की कीमतों के अनुसार 9% की छूट मोदी सरकार ने हासिल कर ली, मगर वो छूट 126 विमानों के लिए नहीं, 36 विमानों के लिए थी.

एक विमान की कीमत तय हुई 91.75 मिलियन यूरो! यह पूरी कहानी नहीं है.

कहानी का बड़ा और दूसरा हिस्सा यह है कि....दास्सों ने कहा कि भारत के हिसाब से विमान को सुसज्जित करने के लिए 1.4 बिलयन यूरो और देने होंगे. भारत ने मोलभाव कर इसे 1.3 बिलियन यूरो पर लाया. भारतीय वायु सेना की मांग थी कि रफाल विमान को 13 विशेषताओं से लैस होना चाहिए ताकि भारत की ज़रूरतों के अनुकूल हो. इसके लिए 36 विमानों के लिए 1.3 बिलियन यूरो देने पर सहमति हुई. इस हिसाब से प्रति विमान की कीमत होती है 36.11 मिलियन यूरो.

2007 में इसकी कीमत थी 11.11 मिलयन यूरो. वायु सेना के जिन विशेषताओं की मांग की थी उनमें UPA और मोदी सरकार के समय कोई बदलाव नहीं आया था.

दि हिन्दू ने इस सौदे से संबंधित रक्षा मंत्रालय के कई दस्तावेज़ देखे हैं. रफाल विमान सौदे के लिए सात सदस्यों की इंडियन नेगोशिएशन टीम (INT) बनी थी. इसके तीन सदस्य कीमत से लेकर कई बातों को लेकर एतराज़ करते हैं. इनके हर सवाल को टीम के बाकी चार सदस्य ख़ारिज कर देते हैं. हर बार 4-3 के अंतर से ही फैसला होता है. ये तीन सदस्य हैं, संयुक्त सचिव और एक्विज़िशन मैनेजर राजीव वर्मा, फाइनेंशियल मैनेजर अजीत सुले, एडवाइज़र(कास्ट) एम पी सिंह. इनका कहना था कि भारत की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार करने के लिए अलग से 1.3 बिलियन यूरो की रकम बहुत ज़्यादा है.

टीम ने इसे खारिज करते हुए लिखा कि भारत के हिसाब से 126 विमानों को तैयार करने के लिए 1.4 बिलियन यूरो दिया जाना था, उससे कहीं बेहतर है 36 विमानों के लिए 1.3 बिलियन यूरो देना.

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रक्षा मामलों की मंत्रिमंडल की समिति ने टीम के फैसले पर मुहर लगा दी.

INT की रिपोर्ट की समीक्षा कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जो नोट दिया है और जिसे याचिकाकर्ताओं को भी दिया गया है, उसके अनुसार सरकार के नोट में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की अध्यक्षता वाली रक्षा ख़रीद परिषद (DAC) की किसी भूमिका का ज़िक्र नहीं है.

यह कैसे हो सकता है जबकि रक्षा ख़रीद प्रक्रिया के तहत DAC को ही फैसले लेने के अधिकार हैं. इसलिए हैरानी की बात नहीं कि 10 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने जब पेरिस में अपनी तरफ से डील का एलान कर दिया तो रक्षा मंत्री खुद को अनजान बता रहे थे!

N Ram का मूल सवाल यह है कि भारत सरकार के पास रफाल से कीमतों को लेकर सौदेबाज़ी करने के कई हथियार थे, उनका इस्तमाल क्यों नहीं किया गया?

4 जुलाई 2014 को यूरोफाइटर के शीर्ष अधिकारी ने रक्षा मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा था कि वह पहले से बेहतर क्षमता से लैस 126 यूरोफाइटर 20% कम दाम पर दे सकता है.

इस पत्र में यह भी लिखा है कि रक्षा मंत्री ने उनके देश के राजदूत से जो गुज़ारिश की उसके जवाब में यह पेशकश करते हुए उन्हें खुशी हो रही थी.

यानी रक्षा मंत्री ने खुद पहल की थी. जबकि INT कमेटी ने यूरोफाइटर के प्रस्ताव को यह कह कर ठुकरा दिया कि यूरोफाइटर ने बिन मांगे प्रस्ताव दिया है, इस वक्त टेंडर बंद हो चुका है और नियमों के अनुकूल इस स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है. कमेटी का यह फैसला सही था या नहीं, इस पर बहस हो सकती है लेकिन सरकार इसे लेकर रफाल से मोल भाव तो कर ही सकती थी.

यूरोफाइटर ने तो यहां तक कहा कि.....वह भारत की ज़रूरतों को देखते हुए जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन और इटली के आर्डर को रोक कर पहले सप्लाई कर देगा.

कमेटी के तीन सदस्यों ने यूरो फाइटर के इस प्रस्ताव को दर्ज भी किया है कि 20% कम दाम पर विमान दे रहा है. UPA के समय जब टेंडर निकला था तब वायु सेना ने यूरोफाइटर का भी परीक्षण किया था. यह जहाज़ भी बेजोड़ पाया गया था मगर उस वक्त कीमतों के कारण पिछड़ गया. रफाल कम कीमत का प्रस्ताव देकर डील के अंदर घुसा और ज़्यादा कीमत पर जहाज़ बेचने की डील कर निकल गया.

इससे किस किस को लाभ हुआ, किसे कितना पैसा मिला, इस बारे में अभी तक कोई रिपोर्टिंग सामने नहीं आई है जैसा कि बोफोर्स के समय हुआ था.

जब यूरो फाइटर 20% कम दाम पर उसी क्षमता का जहाज़ दे रहा था तब 41.42% अधिक दाम पर रफाल से क्यों खरीदा गया? यूरोफाइटर ने यह भी कहा था कि कंपनी भारत में यूरोफाइटर इंडस्ट्रीयल पार्क बनाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएगी और सपोर्ट देगी.

रफाल के साथ हुई नई डील में HAL को भी बाहर कर दिया गया जिसे पहले 108 जहाज़ बनाने थे. N Ram का कहना है कि दास्सों कंपनी के साथ व्यापारिक समझौता नहीं किया जाता है. दो मुल्कों के बीच समझौता होता है मगर संप्रभु गारंटी नहीं ली जाती है. फिर दो मुल्कों के बीच समझौते का क्या मतलब रह जाता है?

संप्रभु गारंटी का मतलब है कि फ्रांस सरकार हर बात की जिम्मेदारी लेती. यही नहीं टेंडर बंद होने की बात कर यूरोफाइटर के प्रस्ताव को ठुकराया गया लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में जो एलान किया वो तो पूरी तरह से नई डील थी!

पहले की प्रक्रियाओं से 126 विमानों की बात हुई थी, अब 36 खरीदे जा रहे थे. ज़ाहिर है उस स्तर पर भी कीमतों को लेकर मोलभाव हो सकता था.

N Ram ने लिखा है कि 2007 में 126 विमानों को भारत के हिसाब से तैयार करने के लिए अलग से 1.4 बिलियन यूरो देने थे. 2016 में 36 विमानों को तैयार करने लिए 1.3 बिलियन यूरो दिए जाने का फैसला होता है. गणित में आप फेल भी होंगे तब भी इस अंतर को समझ सकते हैं कि खेल कहां हुआ है.

इस कारण हर विमान की कीमत 25 मिलियन यूरो बढ़ जाती है. फ्रांस ने बेशक साधारण विमान की कीमत पर 9 ब्र की छूट दी थी लेकिन सुसज्जित विमान की कीम 25 मिलियन यूरो बढ़ा दी गई. यही नहीं पहले के फोलो ऑन क्लाज को हटा दिया गया. इसके तहत 126 विमानों के लिए जो शर्तें तय हुई थीं उन्हीं के आधार और दाम पर 63 विमान और खरीदें जा सकते थे.

ये क्लाज़ किस लिए हटाए गए?

क्यों 36 विमानों को 41.42 % अधिक दामों पर ख़रीदा गया?

45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी के आंकड़े को सरकार ने छुपाना चाहा लेकिन पत्रकार ने सामने ला दिया

रवीश कुमार

2017-18 के लिए नेशनल सैंपल सर्वे आफिस की तरफ से कराये जाने वाले श्रम शक्ति सर्वे के नतीजों को सरकार दबा रही है। इस साल पिछले 45 साल में बेरोज़गारी की दर सबसे अधिक रही है। दिसंबर 2018 के पहले हफ्ते में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) ने सर्वे को मंज़ूर कर सरकार के पास भेज दिया लेकिन सरकार उस पर बैठ गई। यही आरोप लगाते हुए आयोग के प्रभारी प्रमुख मोहनन और एक सदस्य जेवी मीनाक्षी ने इस्तीफ़ा दे दिया है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड के सोमेश झा ने इस रिपोर्ट की बातें सामने ला दी हैं। एक रिपोर्टर का यही काम होता है। जो सरकार छिपाए उसे बाहर ला दे। अब सोचिए अगर सरकार खुद यह रिपोर्ट जारी करे कि 2017-18 में बेरोज़गारी की दर 6.1 हो गई थी जो 45 साल में सबसे अधिक है तो उसकी नाकामियों का ढोल फट जाएगा। इतनी बेरोज़गारी तो 1972-73 में थी। शहरों में तो बेरोज़गारी की दर 7.8 प्रतिशत हो गई थी और काम न मिलने के कारण लोग घरों में बैठने लगे थे।

सेंटर फ़ॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (CMIE) के महेश व्यास तो पिछले तीन साल से बेरोज़गारी के आंकड़े सामने ला रहे हैं। उनके कारण जब बेरोज़गारी के आंकड़ों पर बात होने लगी तो सरकार ने लेबर रिपोर्ट जारी करनी बंद कर दी। उन्होंने पिछले महीने के प्राइम टाइम में बताया था कि बेरोज़गारी की दर नौ प्रतिशत से भी ज़्यादा है जो कि अति है।

आप इंटरनेट पर रोज़गार और रोज़गार के आंकड़ों से संबंधित ख़बरों को सर्च करें। आपको पता चलेगा कि लोगों में उम्मीद पैदा करते रहने के लिए ख़बरें पैदा की जाती रही हैं। बाद में उन ख़बरों का कोई अता-पता नहीं मिलता है। जैसे फ़रवरी 2018 में सरकार अपने मंत्रालयों से कहती है कि अपने सेक्टर में पैदा हुए रोज़गार की सूची बनाएं। एक साल बाद वो सूची कहां हैं।

पिछले साल टीसीए अनंत की अध्यक्षता में एक नया पैनल बना था। उसे बताना था कि रोज़गार के विश्वसनीय आंकड़े जमा करने के लिए क्या किया जाए। इसके नाम पहले जो लेबर रिपोर्ट जारी होती थी, वह बंद कर दी गई। जुलाई 2018 में इस पैनल को अपनी रिपोर्ट देनी थी मगर उसने छह महीने का विस्तार मांग लिया।

इसीलिए बेहतर आंकड़े की व्यवस्था के नाम पर उन्होंने पुरानी रिपोर्ट बंद कर दी क्योंकि उसके कारण सवाल उठने लगते थे। अब जब राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की रिपोर्ट आई है तो उसे दबाया जा रहा है। सोचिए सरकार चाहती है कि आप उसका मूल्यांकन सिर्फ झूठ, धार्मिक और भावुक बातों पर करें।

सरकार की आर्थिक नीतियां फ़ेल हो चुकी हैं। इसलिए भाषण को आकर्षक बनाए रखने के लिए अमरीकी मॉडल की तरह स्टेडियम को सजाया जा रहा है। अच्छी लाइटिंग के ज़रिए प्रधानमंत्री को फिर से महान उपदेशक की तरह पेश किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा और रोज़गार को अपने एजेंडे और भाषणों से ग़ायब कर दिया है। उन्हें पता है कि अब काम करने का मौक़ा भी चला गया।

इसलिए उन्होंने एक तरह प्रधानमंत्री कार्यालय छोड़ सा दिया है। भारत के प्रधानमंत्री सौ-सौ रैलियाँ कर रहे हैं लेकिन एक में भी शिक्षा और रोज़गार पर बात नहीं कर रहे हैं। मैंने इतना नौजवान विरोधी प्रधानमंत्री नहीं देखा। सरकारी ख़र्चे पर होने वाली इन सौ रैलियों के कारण प्रधानमंत्री बीस दिन के बराबर काम नहीं करेंगे। इसे अगर बारह-बारह घंटे में बांटें तो चालीस दिन के बराबर काम नहीं करेंगे। वे दिन रात कैमरे की नज़र में रहते हैं। आप ही सोचिए वे काम कब करते हैं ?

न्यूज़ चैनलों के ज़रिए धार्मिक मसलों का बवंडर पैदा किया जा रहा है ताकि लोगों के सवाल बदल जाएं। वे नौकरी छोड़ कर सेना की बहादुरी और मंदिर की बात करने लग जाएं। हमारी सेना तो हमेशा से ही बहादुर रही है। सारी दुनिया लोहा मानती है। प्रधानमंत्री क्यों बार-बार सेना-सेना कर रहे हैं? क्या सैनिक के बच्चे को शिक्षा और रोज़गार नहीं चाहिए? उन्हें पता है कि धार्मिक कट्टरता ही बचा सकती है। इसलिए एक तरफ अर्ध कुंभ को कुंभ बताकर माहौल बनवाया जा रहा है तो दूसरी तरफ रोज़गार के सवाल ग़ायब करने के लिए अनाप-शनाप मुद्दे पैदा किए जा रहे हैं।

हे भारत के बेरोज़गार नौजवानों ईश्वर तुम्हारा भला करे ! मगर वो भी नहीं करेगा क्योंकि उसका भी इस्तेमाल चुनाव में होने लगा है। तुम्हारी नियति पर किसी ने कील ठोक दी है। हर बार नाम बताने की ज़रूरत नहीं है।

- साइबर नजर

नया सरकारी जुमला- जांच में रोमांच

जांच में रोमांच – यह इस वक्त की नई टैगलाइन है, नया सरकारी जुमला है। वैसे मूलतः यह जुमला अंग्रेजी में कहा गया है- इंवेस्टिगेटिव एडवेंचरिम और इसे देने वाले हैं माननीय अरुण जेटली जी। जो भाजपा सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में शायद यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बजट सत्र तक कोई नया आर्थिक विवाद खड़ा न हो। भाजपा पहले ही 'चौकीदार चोर है', जैसे विपक्षी हमलों से विधानसभा चुनावों में घायल हो चुकी है। इसके अलावा पीएनबी घोटाले के आरोपियों नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की देश से, सरकारी बैंकों में डूबते कर्ज की रकम का बढ़ते जाना ऐसी तमाम बातों से मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों, फैसलों और इरादों पर सवाल खड़े होते रहे हैं। कर्ज और कर्ज डुबाने के मामलों में एक मामला आईसीआईसीआई का भी जुड़ा।

आरोप है कि चंदा कोचर ने आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहते हुए वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ रुपये का ऋण दिया था और इसके बदले में वीडियोकॉन के वेणुगोपाल धूत ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को कारोबारी फायदा पहुंचाया था। इस कर्ज का 86 प्रतिशत हिस्सा यानी लगभग 2810 करोड़ रुपये चुकाया नहीं गया था। इसके बाद, 2017 में आईसीआईसीआई ने वीडियोकॉन के खाते को एनपीए में डाल दिया। यानी 2810 करोड़ रुपए का बट्टा लग गया। इस मामले के खुलासे के बाद इसकी जांच शुरु हुई, और मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की बैंकिंग एंड सिक्योरिटी फ्रॉड सेल ने इस मामले में पिछले दिनों एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में इंवेस्टिगेटिव का जुमला उछालते हुए जांच एजेंसी को नसीहत दी।

श्री जेटली ने लिखा कि भारतीय जांच प्रणाली में दोषियों को अपराध मिलने की दर बहुत कम है। इसका कारण है कि जांच टीमें कई बार प्रशंसा और मीडिया में छाने की इच्छा से आगे बढ़ती हैं, न कि मुख्य दोषी पर शिकंजा करने के उद्देश्य से। जेटली ने ब्लॉग में एफआईआर में कई बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के नाम होने और जांच पर चिंता जताते हुए कहा था, कि यह एजेंसी का जांच के लिए साहसिक अभियान चलाने जैसा मामला है। जांच एजेंसी को मुख्य आरोपियों को निशाना बनाना चाहिए। कोई सामान्य नागरिक, ब्लॉगर, सामाजिक कार्यकर्ता ऐसी बात लिखता तो उसकी मंशा पर सवाल नहीं उठते, लेकिन सरकार में मंत्री पद संभालने वाला कोई इंसान अगर जांच एजेंसी को यह बताए, कि उसे किस तरह से जांच को आगे बढ़ाना चाहिए तो उस पर सवाल उठने लाजमी हैं। और अरुण जेटली ने केवल नसीहत नहीं दी, बल्कि यह भी कस दिया कि प्रशंसा पाने या लाइम लाइट में आने के लिए जांच टीमें ऐसा करती हैं। यह ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों का सरासर अपमान है।

एफआईआर में नाम किसी बढ़ी हस्ती का आये या मामूली इंसान का, असल मकसद तो दोषी तक पहुंचना होना चाहिए। सीबीआई इस वक्त कैसा काम कर रही है और किनके निर्देशों पर कर रही है, कहना कठिन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बैंकिंग एंड सिक्योरिटी फ्रॉड सेल के एस पी सुधांशु धर मिश्रा 22 जनवरी को आईसीआईसीआई धोखाधड़ी मामले में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के वी एन धूत के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराते हैं और 23 जनवरी को उनका तबादला रांची कर दिया जाता है।

सूत्रों के मुताबिक सुधांशु धर मिश्रा पर सीबीआई को गड़बड़ी का संदेह था, इसलिए उनका स्थानांतरण किया गया। सीबीआई की गोपनीय पड़ताल में यह पाया गया कि वह जांच से जुड़ी सूचनाएं लीक कर रहे थे। अगर इतने हाई प्रोफाइल मामले में कोई अधिकारी सूचनाओं को लीक कर रहा है, तो उसका तबादला करने की जगह क्या कुछ दिन निलंबन नहीं करना चाहिए या छुट्टी पर नहीं भेज देना चाहिए? क्या सीबीआई ने उनसे पूछा कि सूचनाएं किसके फायदे के लिए लीक की जा रही थीं? क्या केवल एक अधिकारी के तबादले से सीबीआई यह सुनिश्चित कर सकती है कि आगे गोपनीय सूचनाएं लीक नहीं होंगी? अभी-अभी सीबीआई रिश्वतखोरी विवाद में फंस कर अपनी साख को बट्टा लगा चुकी है, फिर भी देश की सबसे बढ़ी जांच एजेंसी में क्या बिना किसी सतर्कता के काम हो रहा है? गोपनीय सूचनाओं का लीक होने जैसा सच में कोई गंभीर कतरा है या फिर इस तबादले के पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है?

मैं देश का चौकीदार हूं, ऐसा कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी आखिर ऐसा माहौल अपने शासन में क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि जिन पर सच में चौकीदारी का जिम्मा है, यानी देश की सुरक्षा और जांच एजेंसियां बिना किसी दबाव के अपना काम कर सकें। जांच के इस रोमांच में देश पर खतरे की आंच बढ़ रही है, क्या मोदी सरकार यह नहीं देख पा रही है।

-साइबर नजर

लोकसभा चुनाव से पहले भारत में हो सकती है साम्प्रदायिक हिंसा: अमेरिकी खुफिया प्रमुख

अमेरिकी खुफिया प्रमुख डान कोट्स ने अमेरिकी संसद में कहा, भारत में संसदीय चुनाव से पहले यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी हिंदू-राष्ट्रवाद पर अधिक जोर डालती है तो भारत में साम्प्रदायिक हिंसा भड़कने की मजबूत संभावना है.।

अमेरिका के खुफिया प्रमुख का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भारत में साम्प्रदायिक हिंसा हो सकती है. उन्होंने अमेरिकी संसद में अपनी एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें यह कहा गया है।

कोट्स ने अमेरिका के सीनेट सलेक्ट कमिटी ऑन इंटेलिजेंस में वैश्विक खतरों पर आंकलन पेश किया. उन्होंने कहा, मोदी के कार्यकाल में बीजेपी की नीतियों के चलते कई बीजेपी शासित राज्यों में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया है. राज्यों के नेता पार्टी के हिंदू राष्ट्रवादी अभियान को छिटपुट हिंसा भड़काने के सिग्नल के तौर पर देख सकते हैं ताकि इससे समर्थक जुड़े रहें।

खुफिया प्रमुख ने आगे कहा, बढ़ते साम्प्रदायिक हमलों के चलते भारतीय मुस्लिम खुद को अलग-थलग महसूस कर सकते हैं और इससे भारत में इस्लामिक आतंकी समूहों को अपनी जड़ों को मजबूत करने का मौका मिल सकता है।

मोदी सरकार का पांच साल का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है. कोट्स ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि मई तक भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव और अधिक बढ़ सकता है।

राष्ट्रीय खुफिया के निदेशक डान कोट्स ने खुफिया मामलों की सीनेट सलेक्ट कमेटी से कहा कि खुफिया समुदाय के लिए चुनाव सुरक्षा हमेशा प्रमुख रही है और आगे भी बनी रहेगी।

कोट्स ने कहा, ''हमारा आंकलन है कि विदेशी ताकतें अमेरिका में 2020 में होने वाले चुनावों को अपने हितों को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में देखेंगी. हमारा मानना है कि वे अपनी क्षमताओं को और निखारेंगे और उसमें नए दांव पेच जोड़ेंगे क्योंकि वे पूर्व चुनावों में एक दूसरे के अनुभवों और प्रयासों से सीखते हैं.''